संबन्नोबिन विम्ता | 37-87 | 14999. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैंब स्वास्तिका फतौर मिल्ज, यमुनानगर (2) मैंब शिव शंकर ट्रेडिंग कम्पती, यमुनानगर, के श्रीमक श्री रमन कुमार मार्फत श्री इन्द्र सैन बंसल, छस्ता नालागिबिया, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रौद्योगिक विवाद है :

श्रीर चं कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, भोखोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये 'हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3--अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के के अधीन गठित अम नयायालय, अम्बाला, को विवाद प्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री रमन कुमार की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० थ्रो० वि०/यमुना/40-87/15007.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सुपर स्टीम गार्डन, छोटी लाईन, जगाधरी, के श्रमिक श्री सतपाल, पुत्न श्री नत्यू राम, मार्फत डा० सुरिन्द्र कुमार शर्मा, महा मन्द्री मैटल वर्कर, यूनियन, (रिजि०) सम्बंन्धित इन्टक धर्मशाला ग्राहमण, रेलवे रोड़, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रधिसूचना सं० 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 श्रप्रें ल, 1984, द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रयवा सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री सतपाल की छंटनी/सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हिकदार है ?

सं० मो०वि०/रोहतक/55-87/15013.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इस्टर्न लेब्रोट्रीज प्रा० लि०, एम. माई. ई., बहादुरगढ़, जिला रोहतक, के श्रमिक श्री के० सी० श्रम्भाकुट्टी, मार्फत प्रधान एच. एन. जी. मजदूर यूनियन, बहादुरगढ़ (रोहतक) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की घारा 10 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1 श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की घारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा गामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री के. सी. श्रम्भाकुट्टी, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राइत का हकदार है ?

सं भो वि वि (रोहतक/ 59- / 15020 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० इस्टर्न लेब्रोट्रीज प्रा० लि०, एम. ग्राई. ई., बहादुरगढ़, जिला रोहतक, के श्रमिक श्री गंगा प्रसाद, मार्फत प्रधान, एच एम. जी. मजदूर यूनियन, बहादुरगढ़, जिला रोह्नतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, भीचोशिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं० 9641- 1-श्रम- 78/32573, दिनांक 6 नवस्वर, 1970, के साथ गठित सरकारी ग्रिधिसूचना की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसके सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिश्ट करते हैं जो कि उबत प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उदत दिवाद से सुस्रत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री गंगा प्रसाद की सेवाम्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?